उच्च शिक्षा के बदलते आयाम : एक विहंगम दृष्टि

प्रेम प्रकाश यादव,

वरिष्ठ असिस्टेन्ट प्रोफेसर–लाइब्रेरी राजकीय महाविद्यालय, अकबरपुर, कानपुर देहात, उ0प्र0 भारत।

सारांश

शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है, इसके विकास एवं प्रसार की सम्भावना सदैव बनी रहती है शिक्षा धनात्मक तथा ऋणात्मक स्तर से गुजर रही है। एक तरफ 150000 इंजीनियरों में चार फीसदी को रोजगार मिल रहा है, वहीं डॉक्टरों की माँग लगातार देश में बनी हुयी है। इस विषमता को दूर करना होगा तभी देश का विकास हो सकता है। एक ओर शिक्षक के विभिन्न संस्थानों में रिक्त पद चल रहे हैं, और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता की बात हो रही है, ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा के विकास को कैसे गति मिल सकती है। उच्च शिक्षा के त्रिस्तरीय विकास के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित कराना होगा और उच्च शिक्षा को रोजगारपरक तथा व्यवसायपरक करना होगा तभी उच्च शिक्षा तथा युवा/छात्र दोनों का विकास सम्भव है। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 2015–16 में 20से बढ़कर 2017–18 में 25 हो गया। जो शिक्षकों को अतिरिक्त बोझ की तरह प्रतीत हो रहा है। इस विषमता को दूर करके गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का विकास हो सकता है।

Keywords: *शिक्षक, शिक्षार्थी ,पाठ्यक्रम ,उच्च शिक्षा,बदलते आयाम,दृष्टि।*

शिक्षा एक त्रिस्तरीय प्रणाली पर आधारित है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम आते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम के मध्य सामन्जय स्थापित कराना होगा जिससे उच्च शिक्षा को गति मिल सके।शिक्षा एक अनवरत् चलने वाली प्रक्रिया है। जिसके विकास एवं प्रसार की संभावना सदैव बनी रहती है।शिक्षा अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे : व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना तथा पूरे राष्ट्र को चरित्रवान बनाना इत्यादि व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो उसे शिक्षित होना अति आवश्यक है।जिससे वह अधिक निपुणता से कार्य कर सके, स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा का ह्रास कम विकास ज्यादा हुआ है, जो निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

शिक्षा का प्रसार एवं विस्तार होने से हम भौतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं। शिक्षा के विकास ने मनुष्य को विज्ञान से परिचय कराया है जिससे हम अधिक सुविधाजनक जीवन व्यतीत कर रहे है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। जिससे व्यक्ति परिवार एवं समाज पर बोझ नहीं बनता है बल्कि वह स्वयं एक नये पथ को उत्पन्न करता है। शिक्षित होने का मतलब केवल रोजगार या नौकरी पाना ही नहीं बल्कि शिक्षा से व्यक्ति में सोचने,समझने, संघर्ष करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। शिक्षा के सहारे हम अपने चारों ओर तीव्र गति से सुधार कर सकते हैं। विज्ञान के विकास के हम बिजली के उपकरणों द्वारा महीनों या दिनों का कार्य क्रमशः दिनों या घण्टों में कर सकते हैं यह सब शिक्षा की ही देन है।

वर्तमान समय की शिक्षा हमें केवल किताबी ज्ञान ही उपलब्ध नहीं करा रही है बल्कि व्यवहारिक ज्ञान से भी परिचय करा रही है। बल्कि वर्तमान समस्याओं से भी जूझना सिखा रही है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में दिन–प्रतिदिन बदलाव हो रहा है जिससे छात्र अधिक दक्ष हो रहे हैं। समय एवं मांग के अनुसार व्यवसायिक एवं रोजगारपरक शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे छात्र अपने जीवनयापन के साधन ढूंढ़ सके।

शिक्षा में विकास के साथ.साथ बढ़ती अनुशासनहीनता, अराजकता, रैंगिंग, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मूल्यांकन व्यवस्था से शिक्षा का ह्रास हो रहा है–शिक्षा के विकास के साथ–साथ शिक्षा के कुछ ऋणात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जो निम्न हैं :–

1. प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में स्नातक उपाधि धारक तैयार हो रहे हैं। परन्तु उनके रोजगार के साधन दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। जिसके दुष्परिणाम में बेरोजगारी, अपराध, लूटपाट,गुण्डागर्दी में लगातार वृद्धि हो रही है। जो राष्ट्र के लिये चिन्ता का विषय हो रहा है।
2. अधिकतर विश्वविद्यालयों में प्रश्नपत्रों का प्रारूप, उत्तर लिखने की शब्द सीमा, प्रश्नों का अंक विभाजन न्यायसंगत और औचित्यपूर्ण नहीं है। जिससे छात्र गहन अध्ययन न करके केवल पास हो जाते हैं,इससे प्रतिभाशाली छात्र प्रभावित होते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–1949) और कोठारी आयोग (1964–66) ने परीक्षा प्रणाली के सुधार के बारे में कहा है।
3. अधिकांश विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समयानुकूल कोर्स न होने के कारण तथा रोजगारपरक पाठ्यक्रम न होने के कारण शिक्षा के विकास में ऋणात्मक वृद्धि हुई है।
4. छात्रों में बढती अनुशासनहीनता भी शिक्षा के विकास में रूकावट है।
5. शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधा है शिक्षकों के रिक्त पदों को न भरना इससे शिक्षा का प्रसार एवं विकास नहीं हो पा रहा है।
6. कान्ट्रेक्ट या टेम्प्रेरी टीचर सिस्टम से भी शिक्षा प्रभावित हो रही है।

सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उठाये जा रहे कदम इस प्रकार से हैं :–

1. सरकार संस्थानों को स्वायत्तता दे रही है। जिससे संस्थान का विकास तेज गति से हो सके, सरकार की मंशा है कि संस्थान अपने पूर्व छात्रों द्वारा मदद लेकर संस्थान के विकास में गति प्रदान करे। इसी श्रृंखला में में ग्रेडेड स्वायत्तता की ढील दी है, इसके तहत लगभग 70 विश्वविद्यालय ने गुणवत्ता के साथ विकास किया है। इसके तहत संस्थान को अनुमति के लिए सरकार के पास बार–बार नहीं जाना पडता है।वे अपने संस्थान को आवश्यकतानुसार विकास एवं विस्तार कर सकते हैं।
2. उच्चतर अविष्कार योजना के तहत शिक्षक व छात्र साथ.साथ मिलकर विकास कर रहे हैं।
3. देश में जो मेधावी छात्र हैं और विदेश जाकर शोध करते हैं। वे देश में रहकर शोध नहीं करते हैं। वे देश में रहकर शोध कार्य करें इसके लिए सरकार द्वारा प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप शुरू की गयी है। इस वर्ष इस फेलोशिप के तहत 135 छात्रों का चयन किया गया है उन्हे

प्रतिमाह रू0 100000 की सहायता मिलेगी।

4. इसके अलावा स्मार्ट इण्डिया का स्थान है। इस प्रक्रिया के तहत हजारों छात्रों ने मेहनत से अध्ययन करके अनेक समस्याओं का उपाय सुझाया है।

दुनिया ने पिछले लगभग 35 वर्षों में जितने स्नातक छात्र पैदा किये हैं, उतने उससे पहले के लगभग 800 वर्षों में भी स्नातक पैदा नहीं किये गये। पंकज चन्द्रा की महत्वपूर्ण पुस्तक ''बिल्डिंग यूनिवर्सिटीज् दैट मैटर'' से मिलता है। चन्द्रा साहब ये सलाह देते हैं कि :–

1. अच्छे नागरिक तैयार करना।
2. युवाओं और छात्रों को जीवनयापन और वेतन कमाने के लिए तैयार करना।
3. व्यक्तियों को सीखने के लिए जीवनपर्यन्त प्रेरित करना और जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना। शिक्षा का समुचित उपयोग तभी हो सकता है, जब उपरोक्त तीनों बिन्दु सफल हो सके।आज डिग्रीधारी युवा कोरिया में 60 प्रतिशत टैक्सी ड्राइवर, अमेरिका में 31 प्रतिशत क्लर्क और भारत में 15 प्रतिशत सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य कर रहे हैं एक सर्वे से पता चलता है कि 150000 इंजीनियरों में से केवल 4 प्रतिशत ही नौकरी के लिए उपयुक्त पाये गये एक तरफ इंजीनियरों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी तरफ भारत में हर वर्ष अपनी जरूरत से लगभग 100000 से कम डॉक्टर पैदा हो रहे हैं। इससे सामाजिक विषमता पैदा हो रही है। इसे दूर करने की आवश्यकता है। आज विश्वविद्यालयों को नये.नये प्रयोग करने होंगे और राष्ट्र की चुनौतियों से निपटने हेतु जरूरी ज्ञान और व्यवहारिक योग्यता को जोड़ने वाली एक नयी शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। संचार प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल टैक्नोलॉजी की जानकारी तथा इस्तेमाल करने की कुशलता अति आवश्यक है। सूचना और डेटा को हर विषय से जोड़ने का कार्य शिक्षा को गति प्रदान कर सकता है।

वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति बहुत दयनीय दिखाई दे रही है। क्यू0एस0 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 में आई0आई0टी0 मुम्बई 162 वें स्थान पर, आई0आई0टी0 दिल्ली 172 वें स्थान पर तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलूरू 170 वें स्थान पर रहा है। विश्व की शीर्ष 100 शिक्षा संस्थानों में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान शामिल नहीं है। ये चिन्ता का विषय है। 2017–18 में 903 विश्वविद्यालय एवं लगभग 42000 महाविद्यालयों, 502 मेडिकल कॉलेजों, 6446इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी संस्थानों,3265 प्रबन्ध संस्थानों, 1159 एम0सी0ए0 कॉलेजों, 1633फार्मेसी कॉलेजों, 171वास्तुविद संस्थानों,71 कृषि विश्वविद्यालयों,23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, 20 भारतीय प्रबन्ध संस्थानों की एक लम्बी कतार बनती जा रही है। परन्तु उतनी गति से रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिये संस्थानों को रोजगारपरक एवं व्यवसायपरक शिक्षा को विकसित करने की आवश्यकता है।अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे 2017–18 के अनुसार देश के स्नातक/परास्नातक महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयो में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 2015–16 में 15–2 लाख से घटकर तथा 2016–17 में 13–7 लाख तथा 2017–18 में 12–9 लाख रह गयी है। विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात 2015–16 में 20 से बढ़कर 2017–18 में 25 हो गया है। इसके

अलावा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 35 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस ओर गम्भीरता से सोचना होगा।वरना भविष्य में संस्थान होंगे, छात्र होंगे परन्तु रोजगार के साधन न्यूनतम होते जायेगें इसलिये उच्च शिक्षा में संस्थानों की वृद्धि के साथ युवाओं के रोजगार मिलने की सम्भावना प्रबल होनी चाहिए।तभी युवा बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। विकास बढ़ेगा और देश बढ़ेगा डायनासोर इस लिये समाप्त नहीं हुए कि दुनिया बदल गयी, बल्कि इस लिये समाप्त हो गये, क्योंकि वो नहीं बदले।

अतः हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि हमें अति शीघ्र व्यवहारिक, रोजगारपरक एवं राष्ट्र हितैषी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाकर। उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन करना चाहिए जिससे शिक्षा के वृहद स्तर पर गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की बनाते समय इसके सिर्फ शिक्षा जगत के अनुभवी।सुयोग्य,कर्तव्यनिष्ठ,चरित्रवान् तथा उत्कृष्ठ परिणाम देने वाले एवं देशहित में कार्यरत् एवं समर्पित व्यक्तियों को शामिल करना चाहिये। जिससे भारत में शिक्षा का दिनो–दिन विकास हो सके अतः हम कह सकते हैं कि 'जहाँ चाह वहाँ राह' है।

सन्दर्भ सूची

1. इंसानुलहक : एज्यूकेशन एंड इमर्जिन पैटर्न ऑफ पोलाटिकल ओरियन्टेशन रीडिंग इन इडियन सोशियोलॉजी, शेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,2014।
2. बसु, अशोक : एज्यूकेशन सोसल स्ट्रक्चर एंड कल्चर, शेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,2004 ।
3. पाठक, पी0डी0 एवं त्यागी, एस0 डी0–शिक्षा के सिद्धान्त, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 2008।
4. शर्मा, डी0 एल0–उदीयभान भारतीय समाज में शिक्षक, लाल बुक डिपो मेरठ, 2011।
5. सक्सेना, सरोज : शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय आधार, साहित्य प्रकाशन,आगरा, 2011–12 ।
6. चौबे, सरयू प्रसाद : शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 2011।
7. गुप्ता, एस0 पी0 –अनुसंधान सदर्भिका शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2011।
8. लाल, रमन बिहारी तथा शर्मा कृष्ण कान्त : भारतीय शिक्षा का इतिहास : विकास एवं समस्याएँ, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ ।
9. एम0 एच0 आर0 डी0 (1993) शिक्षा बिना बोझ के, नई दिल्ली : भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ।
10. विभिन्न पत्रिकायें जैसे : इण्डिया टुडे, प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण इत्यादि।
11. विभिन्न समाचार पत्र जैसे : दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान इत्यादि ।